# Chapter-9: उपनिवेशवाद और देहात

इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में अपना नियंत्रण स्थापित किया और अपनी राजस्व नीतियों को लागू किया । इस अध्याय में , हम चर्चा करेंगे कि इन नीतियों का लोगों के लिए क्या अर्थ है और इनसे लोगों के दैनिक जीवन में कैसे बदलाव आया ।

**बंगाल और जमींदार :-**

औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था । बंगाल में , ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण समाज को फिर से संगठित करने और नए भूमि अधिकार और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की । इसलिए उन्होंने भूमि संबंधी अधिकारो की नई व्यवस्था लागू की । तथा राजस्व प्रणाली लागू हुई ।

**बर्दवान में कई गई नीलामी :-**

- 1797 में बर्दवान ( वर्तमान बर्धमान ) में एक नीलामी हुई , जिसे ग्रैंड पब्लिक इवेंट के नाम से जाना जाता था ।
- कंपनी ने राजस्व तय किया और प्रत्येक जमींदार को भुगतान करना था । राजस्व का यह निर्धारण स्थायी निपटान के तहत किया गया था और यह वर्ष 1793 से चालू हो गया ।
- जो जमींदार राजस्व देने में असफल रहे , उनकी संपत्ति को राजस्व वसूलने के लिए नीलाम किया गया । लेकिन कभी - कभी यह पाया गया कि नीलामी में खरीदार खुद राजा के नौकर और एजेंट थे , उदाहरण के लिए बर्दवान में नीलामी ।

**राजस्व के स्थायी निपटान की भी आलोचना की गई :-**

- यह जमींदारों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ ।
- इसने कृषकों के हितों को प्रभावित किया ।
- अन्य वर्गों पर करों का बोझ गिर गया ।

**अदा न किए गए राजस्व की समस्या :-**

https://www.evidyarthi.in/

- ब्रिटिश अधिकारी घिर गए कि कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करके कृषि , व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधनों को विकसित किया जा सकता है । यह संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय करके किया जा सकता है ।
- कंपनी को लगा कि जब राजस्व तय हो जाएगा , तो यह व्यक्ति को लाभ कमाने के साधन के रूप में कृषि में निवेश करने का अवसर प्रदान करेगा और कंपनी को राजस्व के नियमित प्रवाह का आश्वासन भी दिया जाएगा ।
- कंपनी के अधिकारियों के बीच लंबे समय तक बहस के बाद , बंगाल और राजस्थान के तालुकादारों के साथ स्थायी समझौता किया गया था ।
- जमींदारों के पास कई , कभी - कभी 400 गाँव भी थे ।
- ज़मींदारों ने अलग - अलग गाँवों से किराया जमा किया , कंपनी को राजस्व का भुगतान किया और अपनी आय के रूप में अंतर को बरकरार रखा ।

**जमींदारों द्वारा भुगतान न करने के कारण :-**

- ज़मींदारों द्वारा राजस्व की अदायगी न करने के लिए कई कारण जिम्मेदार थे जिनमें यह भी शामिल है कि राजस्व की माँगों को बहुत अधिक रखा गया था । यह ऐसे समय में लगाया गया था जब कृषि उपज की कीमतें बहुत कम थीं , इसलिए किसानों को भुगतान करना मुश्किल था ।
- जमींदारों का इलाज भी सख्त कानूनों यानी सूर्यास्त कानून द्वारा किया जाता था , जो पूरी तरह से फसल की परवाह किए बिना था ।
- इस कानून के अनुसार , ज़मींदारों को निर्दिष्ट तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व का भुगतान करना पड़ता था , अन्यथा ज़मींदारी को नीलाम किया जाना था । इनके अलावा , स्थायी बंदोबस्त और कंपनी ने जमींदारों की शक्ति को कम कर दिया । कभी - कभी रैयतों और ग्राम प्रधान - जोतेदार ने जानबूझकर भुगतान में देरी की ।

**कंपनी द्वारा ज़मींदारों पर लागू सीमाएँ :-**

- ज़मींदार कंपनी के लिए महत्वपूर्ण थे , लेकिन यह भी उन्हें नियंत्रित और विनियमित करना चाहता था , उनके अधिकार को वश में करता था और उनकी स्वायत्तता को प्रतिबंधित करता था ।

https://www.evidyarthi.in/

- इस प्रकार , ज़मींदारों की टुकड़ियों को भंग कर दिया गया , सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया और कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में उनकी 'कच्छी ( अदालतें ) लाई गईं ।
- जमींदारों ने स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस को व्यवस्थित करने के लिए अपनी शक्ति खो दी ।
- समय के साथ जमींदारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया और उनकी शक्तियों को जब्त कर लिया गया ।

**गांवों में जोतदारो का उदय :-**

- धनी किसानों के समूह को लोकप्रिय रूप से जोतदारो के रूप में जाना जाता था । जोतदारो अमीर किसानों के एक वर्ग थे ।
- उन्होंने भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण किया , नियंत्रित व्यापार , धन उधार दिया और गरीब किसानों पर अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया । उनकी भूमि की खेती शेयर क्रॉपर के माध्यम से की जाती थी जिसे एडियार या बारगार्ड के नाम से जाना जाता था ।
- गाँव के भीतर जोतदारो की शक्ति जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी । उन्होंने गाँव के जामा को बढ़ाने के जामा के प्रयासों का जमकर विरोध किया और जमींदारी अधिकारी को उनके कर्तव्यों को करने से रोका ।
- कभी - कभी वे जमींदार की नीलाम की गई संपत्ति भी खरीद लेते थे । जोतदारो ने ज़मींदारी व्यवस्था को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

**जमींदारों का प्रतिरोध :-**

- अपने अधिकार को कमजोर करने से रोकने के लिए , ज़मींदार ने अपनी संपत्ति अपनी माता , पत्नी के नाम कर दी नीलामी में हेरफेर किया , राजस्व को जानबूझकर रोक दिया ।
- पुराने रैयत बाहरी लोगों को आने नही देते थे । पुराने जमीदार से खुद को जुड़ा महसूस करते ।
- 19 वी शताब्दी में मंदी का दौर समाप्त हो गया । जो 1790 के दशक की तकलीफ झेल गया वह सफल हुआ उसने अपनी सत्ता मजबूत बना ली ।

https://www.evidyarthi.in/

- राजस्व भुगतान नियम लचीले बनाए गए । जमीदार की सत्ता मजबूत हुई लेकिन 1930 में फिर बही हाल हुआ । तथा जोतदार मजबूत हुए ।

**पांचवें रिपोर्ट और जमींदारों पर इसका प्रभाव :-**

- यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों पर रिपोर्ट की श्रृंखला की पाँचवीं रिपोर्ट थी । इसे 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था । इसमे 1002 पेज थे जिसमें 800 से आधिक में जमीदार तथा रैयतों की अर्जी थी।
- ब्रिटिश संसद ने कंपनी को भारत के प्रशासन पर नियमित रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया और कंपनी के मामलों में पूछताछ करने के लिए समितियों को नियुक्त किया । यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रकृति पर बहसों का आधार बन गया ।
- पांचवीं रिपोर्ट में उस अवधि के दौरान ग्रामीण बंगाल में जो कुछ हुआ , उसके बारे में हमारी धारणा को आकार दिया गया है और 5वीं रिपोर्ट में निहित साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

**बुकानन के लेखे :-**

- फ्रांसिस बुकानन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के तहत विस्तृत सर्वेक्षण किया ।
- बुकानन यात्रा को कंपनी द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसकी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई गई थी । उसे इस बारे में विशिष्ट निर्देश थे कि उसे क्या देखना है और उसे क्या रिकॉर्ड करना है ।
- बुकानन ने पत्थरों , चट्टानों , मिट्टी की विभिन्न परतों , खनिजों और पत्थरों का अवलोकन किया जो व्यावसायिक रूप से मूल्यवान थे ।
- बुकानन ने परिदृश्य के बारे में लिखा था कि कैसे इन परिदृश्यों को रूपांतरित किया जा सकता है और उत्पादक बनाया जा सकता है ।
- उनके आकलन को कंपनी के वाणिज्यिक हित और आधुनिक पश्चिमी धारणाओं द्वारा आकार दिया गया था जो कि गठित प्रगति थी । वह वनवासियों की जीवनशैली के आलोचक थे ।

https://www.evidyarthi.in/

**बंगाल के देहाती क्षेत्र :-**

धीरे - धीरे समय बीतने के साथ , खेती का विस्तार हुआ और राजमहल पहाड़ियों में चरागाह और जंगल को निगलते हुए खेती के क्षेत्र में पहुंच गया । स्थानांतरण की खेती कुदाल की मदद से की गई , जबकि हल से जुताई की गई ।

**राजमहल की पहाड़िया :-**

- फ्रांसिस बुकानन , एक चिकित्सक ने राजमहल पहाड़ियों के माध्यम से यात्रा की और उन्होंने इसके बारे में एक खाता दिया ।
- मूल रूप से राजमहल पहाड़ियों में पहाड़िया रहते थे । वे शिकार पर रहते थे , खेती को स्थानांतरित कर रहे थे , भोजन एकत्र कर रहे थे और अंतरंग रूप से जंगल से जुड़े हुए थे ।
- 18 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अंग्रेजों ने जंगल की निकासी को प्रोत्साहित किया और जमींदार और जोतदार ने भी असिंचित भूमि को चावल के खेतों में बदलना शुरू कर दिया । जैसे - जैसे कृषि का विस्तार हुआ , जंगल और चारागाह का क्षेत्र सिकुड़ता गया इससे पहाड़ियों और बसे हुए किसानों के बीच संघर्ष तेज हो गया ।
- 1780 के आसपास , संथाल इन क्षेत्रों में आ गए । उन्होंने जंगल साफ किए और जमीन की जुताई की ।
- संथाल वहॉ बसने के द्वारा निचली पहाड़ियों को हटाए जाने के बाद , पहाड़ियों ने राजमहल पहाड़ियों में आंतरिक भाग लिया ।

**संथाल लोगो के बसने के बाद :-**

- जमींदारों और अंग्रेजों ने पहाडियों को वश में करने में असफल होने के बाद उन्हें संथालों में बदल दिया । संथाल आदर्श बसने वाले दिखाई दिए , जंगल को साफ किया और भूमि को समतल किया ।
- भूमि प्रदान किए जाने के बाद , संथालों की आबादी तेजी से बढ़ी और उनके गाँव भी संख्या में बढ़ गए ।

https://www.evidyarthi.in/

- जब संथाल बस रहे थे , तो पहाड़ियों ने विरोध किया , लेकिन अंततः पहाड़ियों में गहरी वापसी के लिए मजबूर होना पड़ा । इसने दीर्घकाल में पहाड़ियों को प्रभावित किया ।
- संथाल अब एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे , उन्होंने बाजार के लिए कई प्रकार की फसलों की खेती की और व्यापारियों , साहूकारों से निपटा लेकिन राज्य उन पर बहुत अधिक कर लगा रहे थे , साहूकार ( दिकस ) उच्च ब्याज दर वसूल रहे थे और कर्ज न चुकाने पर अपनी जमीन ले रहे थे और जमींदार अपनी जमीन पर नियंत्रण कर रहे थे ।
- बाद में समस्याओं के कारण , संथाल ने वर्ष 1855 - 1856 में विद्रोह किया , और उन्हें शांत करने के लिए , अंग्रेजों ने संथालों के लिए नए क्षेत्रों को तराशा और इसके भीतर कुछ विशेष कानून लागू किए ।

**बॉम्बे डेक्कन देहात में विद्रोह :-**

- बॉम्बे डेक्कन के क्षेत्र में क्या हो रहा था , इसका पता लगाने का एक तरीका उस क्षेत्र के विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना है । विद्रोहियों ने गुस्सा और रोष व्यक्त किया ।
- विद्रोह किसान के जीवन , विद्रोह से जुड़ी घटना , विद्रोह को दबाने या नियंत्रण के बारे में जानकारी प्रदान करता है । इतिहासकारों द्वारा खोजे जा सकने वाले विद्रोह के परिणाम के बारे में पूछताछ ।
- उन्नीसवीं सदी के माध्यम से , भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने धन उधारदाताओं और अनाज डीलरों के खिलाफ विद्रोह में वृद्धि की , उदाहरण के लिए दक्कन में 1875 में विद्रोह हुआ ।
- 1895 में पूना के सुपा गाँव में एक आंदोलन शुरू हुआ , जहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों के दंगाई इकट्ठा हुए और उन्होंने दुकानदारों पर हमला किया और उनके बही खातो ( खाता बही ) और ऋण बांड की माँग की । रयोट्स ने खातो को जलाया , लूटी गई दुकान और कुछ उदाहरणों में साहूकारों के घर को जला दिया ।
- बाद में पुणे से अहमदनगर तक विद्रोह फैल गया और आगे भी भयभीत साहुकार अपनी संपत्ति और अपने पीछे छोड़ते हुए गाँव भाग गए ।

https://www.evidyarthi.in/

- ब्रिटिश अधिकारियों ने इन विद्रोहों को नियंत्रित किया , उन्होंने गांवों में पुलिस चौकी स्थापित की और लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें दोषी ठहराया ।

**एक नई राजस्व प्रणाली शुरू हुई :-**

- 19 वीं शताब्दी में , ब्रिटिश कंपनी अन्य अस्थायी राजस्व निपटान नीतियों के माध्यम से अपने अनुमानित क्षेत्रों में अपने वित्तीय संसाधनों का विस्तार करने की इच्छुक थी ।
- ऐसा इसलिए था , क्योंकि 1810 के बाद , कृषि कीमतों में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आय बढ़ी लेकिन कंपनी नहीं । यह स्थायी निपटान नीति के कारण था जिसमें राजस्व की मांग तय की गई थी और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता था । इसलिए अपने राजस्व स्रोत का विस्तार करने के लिए , कंपनी ने अस्थायी निपटान शुरू किया ।
- अधिकारियों की नीतियां भी आर्थिक सिद्धांतों से परिचित थीं , जिनसे वे परिचित हैं । 1820 के दशक में , अधिकारी रिकार्डियन विचारों के प्रभाव में थे । डेविड रिकार्डो इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे ।
- रिकार्डियन विचार में कहा गया है कि ज़मींदार को केवल औसत किराए का दावा करना चाहिए और जब अधिशेष है , तो राज्य को उस अधिशेष पर कर लगाना चाहिए । वह आगे कहते हैं कि अगर कर नहीं लगाया जाएगा तो खेती करने वालों को किराए पर लेने की संभावना होगी और जमीन के सुधार में अधिशेष आय का उत्पादन उत्पादकता में नहीं होगा ।
- रायोटवारी बस्ती को एक नई राजस्व प्रणाली के रूप में बॉम्बे डेक्कन में पेश किया गया था । इस प्रणाली में , राजस्व सीधे कृषक या रैयत के साथ तय किया गया था । मिट्टी से औसत आय , राजस्व की राजस्व भुगतान क्षमता का आकलन किया गया था और इसका अनुपात राज्य के हिस्से के रूप में तय किया गया था । इस प्रणाली में , प्रत्येक 30 वर्षों में भूमि के पुनरुत्थान का प्रावधान था ।

**राजस्व की मांग और किसान कर्ज़ :-**

https://www.evidyarthi.in/

- राजस्व की मांग बहुत अधिक थी और जब फसल खराब थी , तो भुगतान करना असंभव था जब किसान राजस्व का भुगतान करने में विफल रहा , तो उसकी फसलों को जब्त कर लिया गया और पूरे गांव पर जुर्माना लगाया गया ।
- 1830 में , कीमतों में तेजी से गिरावट आई , अकाल मारा गया और इस वजह से डेक्कन में 1/3 पशुओं की मौत हो गई और मानव आबादी का आधा हिस्सा मर गया । तो समस्या बहुत गंभीर हो गई , लेकिन अवैतनिक राजस्व बढ़ गया । इन स्थितियों में कई किसान अपने गांव को छोड़कर नए स्थानों पर चले गए ।
- एक परेशान अवधि में , विवाह की व्यवस्था के लिए चीजों को खरीदने के लिए और कृषि शुरू करने के लिए , किसान को पैसे की जरूरत थी । इसलिए उन्होंने साहूकार से पैसे उधार लिए । लेकिन एक बार ऋण लेने के बाद , वे इसे वापस भुगतान करने में असमर्थ थे । जैसे - जैसे कर्ज चढ़ता गया और कर्ज चुकता होता गया , साहूकार पर किसान निर्भरता बढ़ती गई ।
- 1840 तक , अधिकारियों ने पाया कि किसान अनिश्चितता के खतरनाक स्तर पर थे , इसलिए उन्होंने राजस्व की मांग को थोड़ा कम कर दिया । 1845 तक , कृषि मूल्य लगातार कम हो गया और किसानों ने खेती का विस्तार करना शुरू कर दिया । लेकिन विस्तार के उद्देश्य से उन्हें बीज आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी , इसलिए उन्होंने फिर से धन के लिए साहूकार की ओर रुख किया ।

**कपास और इसकी वैश्विक स्थिति :-**

- 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया । युद्ध के कारण , ब्रिटेन को कपास का निर्यात बहुत कम हो गया । अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में कपास खेती को बढ़ावा दिया गया ।
- निर्यात व्यापारियों ने शहरी साहूकारों को पैसा दिया जिन्होंने बदले में ग्रामीण साहूकारों को उपज सुरक्षित करने के लिए दिया । इसलिए अब किसान के पास पैसे आसानी से पहुंच रहे थे और इस वजह से कपास का उत्पादन तेजी से बढ़ा ।

https://www.evidyarthi.in/

- लेकिन इससे ज्यादातर अमीर किसानों के लिए समृद्धि आई और छोटे किसानों के लिए यह भारी कर्ज का कारण बना । 1862 तक ब्रिटेन में 90 प्रतिशत से अधिक कपास का आयात भारत से हो रहा था ।
- जब 1865 में गृहयुद्ध समाप्त हुआ , तो कपास का निर्यात फिर से शुरू हुआ , कपास की कीमतें और भारत से कपास की मांग में कमी आई । इस प्रकार व्यापारी , साहूकार और साहूकार किसानों को ऋण नहीं दे रहे थे , इसके बजाय उन्होंने कर्ज चुकाने की मांग की । वहीं राजस्व की मांग भी 50 से 100 प्रतिशत तक बढ़ गई थी ।

**किसानों के अन्याय का अनुभव :-**

- किसान गहरे और गहरे कर्ज में डूब गए और अब वे जीवित रहने के लिए साहूकार पर पूरी तरह निर्भर थे लेकिन अब साहूकार उनके ऋण को मना कर रहे थे । इसके साथ ही , प्रथागत नियम था कि जो ब्याज लिया जाता है , वह ऋण की मूल राशि से अधिक नहीं हो सकता है । लेकिन औपनिवेशिक शासन में यह कानून टूट गया था और अब रैयतों ने धन उधारदाताओं को कुटिल और धोखेबाज के रूप में देखना शुरू कर दिया था । उन्होंने साहूकारों से कानूनों में हेरफेर करने और खातों को जाली बनाने की शिकायत की ।
- इस समस्या से निपटने के लिए , 1859 में ब्रिटिश ने लिमिटेशन लॉ पास किया जिसमें कहा गया था कि लोन बॉन्ड की वैधता केवल 3 साल होगी ।
- यह ब्याज के संचय की जांच करने के लिए था । लेकिन साहूकारों ने अब हर 3 साल में एक नई बाध्यता पर हस्ताक्षर करने के लिए रैयत को मजबूर किया , जिसमें पिछले ऋण के कुल अवैतनिक शेष को मूल राशि के रूप में दर्ज किया गया था और उस पर ब्याज लगाया गया था ।
- दक्कन दंगा आयोग की याचिकाओं में कहा गया है कि कैसे साहूकार ऋण वापस भुगतान किए जाने पर रसीद देने से इनकार करके उन्हें दबा रहे थे और उन पर अत्याचार कर रहे थे , उन्होंने बांड में काल्पनिक आंकड़े दर्ज किए और उन्हें बांड या दस्तावेज पर अंगूठे का निशान लगाने के लिए मजबूर किया , जिसके बारे में उन्हें कोई पता नहीं था और वे पढ़ने में सक्षम नहीं थे ।

https://www.evidyarthi.in/

- धन उधारदाताओं ने भी कम कीमत पर फसल का अधिग्रहण किया और अंततः किसान की संपत्ति पर कब्जा कर लिया । जीवित रहने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उन्हें जरूरत थी ।

**दक्कन दंगा आयोग और उसकी रिपोर्ट :-**

- बंबई सरकार ने दक्कन में एक दंगे की जाँच के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग ने जिले में जिज्ञासुओं को रखा जहां दंगा फैला , रैयत , साहूकारों और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए , राजस्व दर पर डेटा संकलित किए गए , विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दर और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट मिलीं। आयोग की रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी।
- इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक सरकार की आधिकारिक सोच परिलक्षित हुई। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसान साहूकारों द्वारा नाराज थे, न कि कंपनी की राजस्व माँग से । यह दर्शाता है कि औपनिवेशिक सरकार यह स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थी कि लोकप्रिय असंतोष सरकारों की कार्रवाई के खिलाफ था । आधिकारिक रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण का अमूल्य स्रोत हैं लेकिन उन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ भी जूझने की जरूरत है।

evidyarthi
https://www.evidyarthi.in/